मोदी समर्पण और सत्ता समीकरण

मोदी रूपी स्तम्भ पर टिकी भाजपाई सत्ता का उस दिन क्या होगा जिस दिन यह स्तम्भ ही धराशाही हो जायेगा? लगभग तमाम राज्यों के विधायक और सांसद मोदी के नाम पर वोट लेकर चुनाव जीत कर आये हैं। हर चुनाव में मोदी कहते रहे हैं कि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले को न देख कर केवल उनके चेहरे को देखें, यानी मतदाता अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहा वह तो केवल मोदी को वोट दे रहा है। ऐसे में भला चुनाव जीतने वाले सांसद एवं विधायक की क्या औकात रह सकती है? उसकी हैसियत एक राजनीतिक बंधक से अधिक कुछ नहीं हो सकती। वह अपने क्षेत्र में तो भले ही निजी स्वार्थों की पूर्ति एवं लूट-मार कर सकता है परन्तु सरकार की नीतियों एवं कार्यान्वयन में उसका कोई दखल नहीं रह पाता। इन हालात में चुने हुए जन प्रतिनिधियों का जनता से कट जाना स्वाभाविक है।

जब 56 इन्च की छाती वाला स्तम्भ जो कहता हो 'मैं ही सब कुछ हूं', धराशाही हो जाये तो उन बाकी लोगों का क्या होगा जो केवल उसी के बूते खड़े थे? जाहिर है, वे सब तो धूल की तरह उड़ जायेंगे। किसान आन्दोलन ने जिस तरह मोदी के घुटने टिकवाये हैं, उससे प्रकट हो रहा है कि फ़िलहाल टिके हुए घुटने बहुत जल्द टूटने वाले हैं। फ़ासीवादी गुंडा-गिरोह की शक्ल अख्यार कर चुकी मोदी सरकार के राज में, तमाम जुल्मो सितम के बावजूद, आम लोग आन्दोलन करना भूल चुके थे। औद्योगिक मज़दूर, रेलवे और बैंक कर्मचारियों सहित किसी भी यूनियन को मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ा गया था। नागरिकता कानून को लेकर चले आन्दोलन को मोदी सरकार ने कोरोना हथियार से कुचल दिया था।

इस सबके बावजूद पंजाब से उठी किसान आन्दोलन की एक छौटी सी लहर देखते ही देखते सुनामी बन गयी। मोदी गिरोह ने इसे हल्के में लेते हुए साम, दाम, दंड भेद की नीति अपनाते हुए हर तरह से कुचलने का प्रयास किया। परन्तु मोदी का हर प्रयास मानो इस आन्दोलन के लिये खाद-पानी का काम कर गया; मोदी की हर कुटिल चाल के बाद इसका स्वरूप निखरता गया और ताकत बढती गयी। मोदी की तमाम अपेक्षाओं के विरुद्ध आन्दोलन की बढती तपिश उनके लिये असहनीय होने लगी। यूपी का चुनाव उन्हें इस तपिश में जल कर राख होता नज़र आने लगा था, जिस मोदी के लिये भीड़ मोदी-मोदी चिल्लाते हुए स्वत: आया करती थी, अब दिहाड़ी व खाना-खुराक देकर बसों में लाद कर लानी पड़ रही है और यह भीड़ भी रैली में बैठने के बजाय इधर-उधर भटकती दिखी।

दीवार पर लिखी इस इबारत को समझ कर मोदी ने किसानों के आगे घुटने टेक कर किसान आन्दोलन की तपिश को समाप्त करना चाहा था, परन्तु आन्दोलन की यह आग तो जंगल की उस आग की तरह फ़ैलने लगी जिस पर डाला गया पानी भी पेट्रोल का सा काम करने लगता है। किसान आन्दोलन समाप्त होने की बजाय मजबूत होने लगा, इतना ही नहीं जो बैंक कर्मी, रेलवे कर्मी तथा अन्य सताये हुए मज़दूर संगठन आन्दोलन करने से डरते थे, अब उनके हौसले भी बुलंद होने लगे। शीघ्र ही डरे, थमे आन्दोलनों की बाढ आने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। हालात ठीक उस मरखने सांड जैसे बनते नज़र आ रहे हैं जिसे देख कर सब लोग डर के मारे रास्ता छोड़ देते थे। परन्तु जब ग्रामीणों ने एकजुट होकर लठ उठाये तो सांड भाग खड़ा हुआ। और भागते हुए सांड को लोगों द्वारा खूब लठियाया भी गया।

आने वाले चुनावों में यू पी, उत्तराखंड, पंजाब व गोआ के जो हालात नज़र आ रहे हैं, भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह साफ़ होने वाला है। जिस व्यक्तिगत करिश्में के घमंड में मोदी उछलते घूम रहे थे, उसके धराशाही होने के बाद उन सब मंत्रियों सांसदों व विधायकों का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है जो आज मोदी के सामने घुटनों पर रहते हैं। कहने को तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे चंद वयोवृद्ध नेता ही मार्ग दर्शक मंडल में बैठाये गये हैं, परन्तु वास्तव में अमितशाह व नितिन गडकरी को छोड़ कर तमाम मंत्री, सांसद व भाजपाई मुख्यमंत्री मार्ग दर्शक मंडल में ही बैठा दिये गये हैं। ये तमाम मोदी की हां में हां मिलाने और उनके इशारों पर नाचने मात्र को रह गये हैं।

लेकिन मार्च 2022 में जब करिश्मे का ढोल फट जाये तो मार्ग दर्शक मंडल में बैठे तमाम लोग यदि अपने आप को आजाद घाषित कर दें और खुद राजनीतिक फ़ैसले लेने लगें तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिये। ऐसा करना उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी क्योंकि जिस मोदी तिलिस्म के सहारे वे राजनीति करते आ रहे थे, उसके खत्म हो जाने पर, अपनी राजनीति बचाने के लिये उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। यदि ऐसा होता है तो पूरी भाजपा में भगदड़ मचनी स्वाभाविक है। ऐसे हालात में मोदी की सरकार कितने दिन ठहर पायेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी चल पायेगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। जब मोदी सरकार ही संकट में आ जायेगी तो हरियाणा व मध्य प्रदेश जैसी डांवाडोल सरकारें कैसे टिकी रह सकेंगी यह और भी बड़ा प्रश्न है।

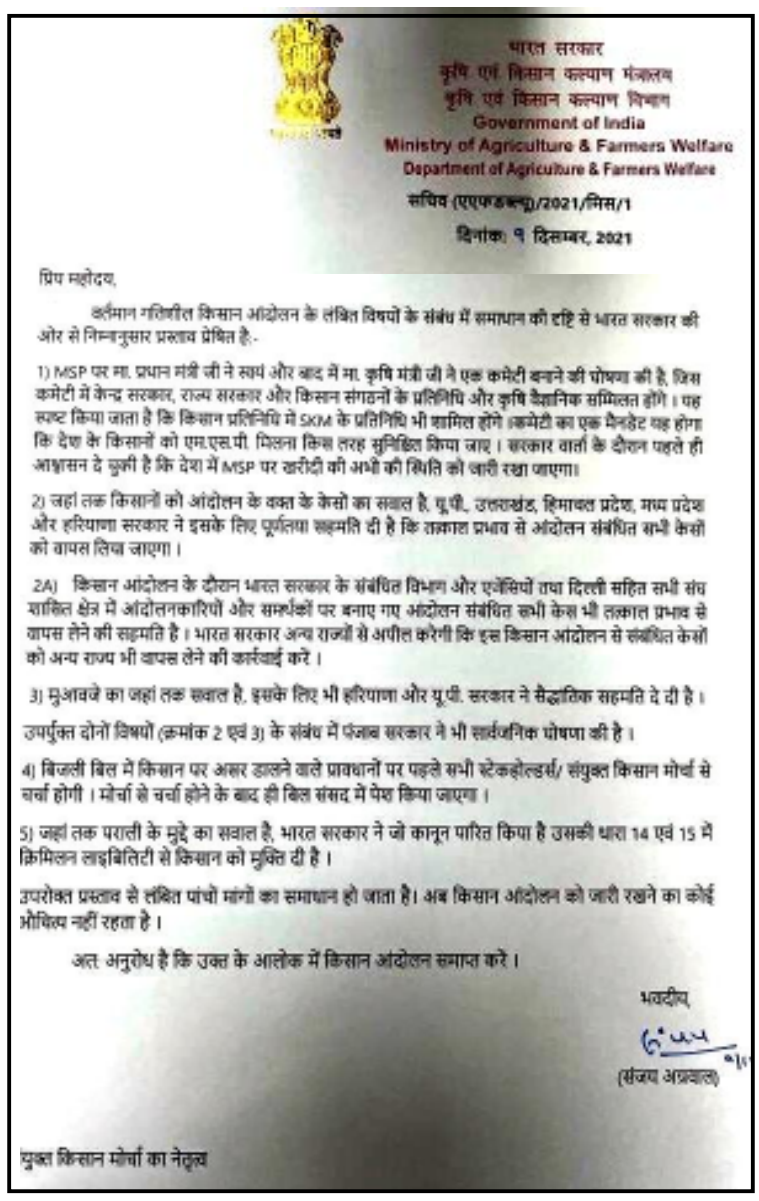

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare

संचिव (एएफडब्लू)/2021/मिस/1

दिनांक: 9 दिसम्बर, 2021

प्रिय महोदय,

वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है:-

1) MSP पर मा. प्रधान मंत्री जी ने स्वयं और बाद में मा. कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में SKM के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैनडेट यह होगा कि देश के किसानों को एम.एस.पी. मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में MSP पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा।

2) जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यू.पी., उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा।

2A) किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्र में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों को अन्य राज्य भी वापस लेने की कार्रवाई करें।

3) मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यू.पी. सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

उपर्युक्त दोनों विषयों (क्रमांक 2 एवं 3) के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है।

4) बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेकहोल्डर्स/ संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा।

5) जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है।

उपरोक्त प्रस्ताव से लंबित पांचों मांगों का समाधान हो जाता है। अब किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अत: अनुरोध है कि उक्त के आलोक में किसान आंदोलन समाप्त करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)

संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व

भाजपाई भले नहीं, आने वाले कौन से भले होंगे?

भाजपा सरकारें 2022 में गिरें या 2024 में, सवाल यह बड़ा है कि इनकी जगह आने वाले कौन से भले होंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टियों सहित लगभग सभी पार्टियों को देश की जनता खूब अच्छी तरह देख चुकी है। कांग्रेसी भले होते तो संघी भेड़िये भेड़ का मुखौटा लगा कर कभी न आ पाते। कांग्रेसी कुशासन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार व घोटालों को भुगतने के चलते जनता को भाजपा के लुभावने जुमलों ने लुभा लिया और लुभा भी इस तरह लिया कि विपक्ष का पूरी तरह सफ़ाया करके इन्हें निरंकुश तानाशाह बना दिया।

इस सारे खेल में पूंजी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही। पूंजी के बल पर न केवल सारा मीडिया खरीद लिया गया बल्कि भाजपा नेतृत्व को भी खरीद लिया गया। यह पूंजी का ही कमाल था कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छीन कर मोदी-शाह जैसे जरायम-पेशा लोगों को सौंप दी गयी। जिस मोदी को, 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म सिखाना चाहते थे वह खुद ही राजधर्म की मूरत बन बैठा।

आखिर यह सब क्या था? पूंजीवाद के इस युग में पूंजीपति अपने पूंजी प्रसार एवं मुनाफ़े के लिये सत्ता पर पूरा नियंत्रण बना कर चलता है जिससे कि सरकार तमाम नीतियां उनके हितों को साधने के लिये ही बनाये; देश के तमाम संसाधन, खदानों से लेकर बैंकों तक सब, उन्हीं के लिये होकर रह जायें। पूंजीपति अपने संसाधनों के बल पर तमाम तरह से राजनीतिक विश्लेषण एवं खोजबीन करके यह पता लगाते रहते हैं कि कब कौन सी पार्टी एवं कौनसा नेता उनके काम का है, यानी कौन उनके कारोबार एवं मुनाफ़े को अधिक से अधिक बढा पायेगा। इसी विश्लेषण के आधार पर ये लोग अपने पैसे का राजनीति में निवेश करतें हैं।

सन 2012-13 तक पूंजीपति वर्ग समझ चुका था कि कांग्रेस अब उनके हितों को और आगे बढा पाने की स्थिति में नहीं है। स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इस वर्ग ने कांग्रेस विरोध एवं संघ-भाजपा पर पैसा लगाना शुरू किया था। अन्ना आन्दोलन भी उसी रणनीति का हिस्सा था। रही बात भाजपा के भीतर आडवाणी और मोदी में से चुनने की तो पूंजीपतियों को जो सम्भावनायें मोदी जी में नज़र आ रही थीं, वे आडवाणी में नहीं थीं। आडवाणी न तो आपराधिक पृष्ठ भूमि से आते हैं और न ही अनपढ़ हैं। वे, और चाहे जैसे भी हों लेकिन लोकतान्त्रिक समझ तो रखते ही हैं। परिस्थितियों में पूंजीपतियों को मोदी में ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति नज़र आया, जो सब कुछ ताक पर रख कर, हर कीमत पर उनके हितों को, पूरी बेशर्मी से आगे बढा सकेगा, सो उन्होंने एकजुट होकर मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया। उनका यह दाव पूरी तरह शायद उनकी अपेक्षाओं से भी बढ़कर निकला।

कृषि 'सुधार' कानून पूंजीपतियों का पुराना एजेंडा है

न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक पूंजीवाद कृषि 'सुधारों' के नाम पर अमेरिकी तर्ज पर किसानों को ज़मीन से बेदखल करके उनकी ज़मीनों को पूंजीपतियों के हवाले कराने का इच्छुक रहा है। कृषि का मशीनीकरण करके तमाम किसानों को खेती-बाड़ी से फ़ारिग कर शहरी मज़दूर बनाना चाहता है जिससे बेरोजगारी बढेगी और औद्योगिक मज़दूर सस्ते मिलेंगे। भारत में जहां 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं वही अमेरिका में मात्र तीन प्रतिशत लोग ही इस पर निर्भर हैं।

यद्यपि यह काम कांग्रेस के एजेंडे पर भी था लेकिन उनकी कमज़ोर क्रियान्वयन स्थिति को भांपते हुए भारतीय एवं वैश्विक पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस की जगह किसी ऐसी पार्टी एवं नेता को आगे लाने की योजना बनाई जो इस 'सुधार' कार्य को पूरा कर सके। संघ द्वारा पोषित भाजपा और उसमें मोदी को सबसे फ़िट समझा गया। संघ एवं भाजपा के पास दो

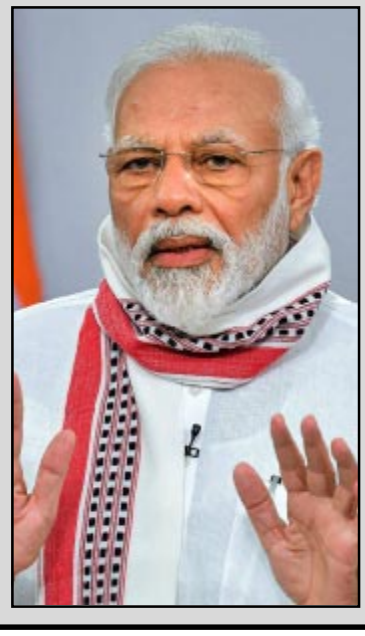

सबसे बड़े हथियार के रूप में थे, धर्म की अफ़ीम और प्रचार द्वारा जनता को भ्रमित करने का नायाब नुस्खा। पूरे पांच साल हिंदुत्व की अफ़ीम खिला व राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला कर मोदी पूरी तरह से आश्वस्त हो गये थे कि अब उनके द्वारा लाये जाने वाले कृषि कानूनों के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, परंतु किसानों ने उन्हें न केवल पूरी तरह से ग़लत साबित कर दिया बल्कि उनकी कुर्सी तक पर संकट छा गया।

किसान आन्दोलन का चुनावी लाभ उठाने के लिये तो सभी दल तरह-तरह की लफ़्फ़ाजी कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी वाला कानून बना कर देने का वायदा कोई पार्टी नहीं कर रही। दरअसल इस तरह का कानून बनाने का बायदा करके कोई भी पार्टी पूंजीवादियों खास कर वैश्विक पूंजीवाद यानी अमेरिका से सीधी दुश्मनी नहीं ले सकती।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06